

रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने के लिए शेख हसीना ने भारत से मांगी मदद

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के शांतिनिकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शिरकत की। शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश चाहता है कि अब जितना जल्द हो सके रोहिंग्या शरणार्थियों अपने देश वापस लौट जाएं और भारत भी म्यांमार से बात करवाने में मदद करे। रोहिंग्या शरणार्थियों की बात उठाते हुए बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने भारत की मदद मांगी। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों ने बांग्लादेश में आसरा लिया हुआ है। हमने उन्हें इंसानियत के नाते जगह दी। हम चाहते हैं कि जितनी जल्द हो सके, वे अपने देश लौट जाएं। मैं चाहती हूँ कि आप (भारत) म्यांमार से हमारी बातचीत करवाने में मदद करे ताकि वे रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस अपने देश ले जा सकें। बता दें कि दीक्षांत समारोह के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और शेख हसीना ने 25 करोड़ रुपये की लागत से बने बांग्लादेश भवन का भी उद्घाटन किया। पीएम ने इस मौके पर कहा कि शायद यह पहला मौका है, जब किसी दीक्षांत समारोह में दो देशों के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। भारत और बांग्लादेश एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी और शेख हसीना एक द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, बांग्लादेश के करीब 150 प्रतिनिधि दीक्षांत समारोह और बांग्लादेश भवन के



उद्घाटन के लिए यहां पहुंचे हैं। तीस्ता नदी बंटवारे पर नहीं होगी बात : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा था कि वह शनिवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात करेगी लेकिन तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि तीस्ता नदी पर चर्चा के लिए इस कार्यक्रम के दौरान कोई जगह नहीं है। पीएम मोदी ने मांगी माफी : इससे पहले शांतिनिकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने असुविधा के लिए छत्रों से क्षमा मांगी। बांग्ला में अपने संबोधन की शुरुआत करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं चांसलर होने के नाते यहां हुई असुविधाओं के लिए क्षमा मांगता हूँ। जब वह आ रहे थे तो रास्ते में कुछ बच्चों इशारों में कह रहे थे कि यहां पीने का पानी भी नहीं है। मैं आप सबसे इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। ममता बनर्जी को पीएम ने दिखाया रास्ता : पीएम हेलिकॉप्टर से उतरते तो राज्य के गवर्नर केशरी नाथ त्रिपाठी ने उनका स्वागत किया। पीएम ने देखा तो कुछ दूरी पर उन्हें सीएम ममता बनर्जी तेजी से आती दिखीं। प्रधानमंत्री मोदी भी उनकी तरफ आगे बढ़ गए। इस दौरान तेजी से आ रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पीएम मोदी ने सही रास्ता दिखाया क्योंकि आगे रास्ता खराब था। उन्होंने इशारों में कहा कि आप इधर से आइए।

शिवसेना ने बीजेपी को बताया 'पागल हत्यारा'

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के शिवसेना पर धोखा देने का आरोप लगाए जाने के कुछ दिन बाद ही शिवसेना ने भाजपा को 'सनकी खूनी' बताया है। शिवसेना ने कहा कि इसके रास्ते में जो भी आ रहा है वह उसे खंजर मार रही है। शिवसेना ने विरार में रैली के दौरान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी की तस्वीर पर माल्यार्पण के दौरान अपनी खड़ाऊं रूचीपल नहीं उतारने के लिए उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निंदा की। 28 मई को पालघर लोकसभा उपचुनाव के लिए योगी रैली करने आये थे। शिवसेना ने अपने मुख्या 'सामना' में कहा कि उत्तर प्रदेश के

दोंगी मुख्यमंत्री ने चुनाव अभियान के लिए पालघर का दौरा किया और कहा कि शिवसेना ने भाजपा की पीठ में खंजर घोंपा। यह दिखाता है कि वह छत्रपति शिवाजी के इतिहास को नहीं समझ पाए हैं। फडणवीस ने हाल में कहा था कि शिवसेना ने पालघर लोकसभा उपचुनाव में दिवंगत सांसद चिंतामन वनाग के पुत्र को चुनाव मैदान में उतारकर भाजपा को धोखा दिया है। शिवसेना ने कहा कि भाजपा ने पालघर उपचुनाव के लिए कांग्रेस के पूर्व नेता राजेन्द्र गावित को उम्मीदवार बनाने का कृत्य किया और भाजपा सेना के खिलाफ बोल रही है।

मूड ऑफ द नेशन: केंद्र में फिर मोदी सरकार, लेकिन बैसाखी जरूरी होगी इस बार

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने चार साल पूरे कर लिए हैं। 26 मई 2014 को मोदी सरकार ने शपथ ली थी, और इस बार सरकार ने अगले चुनाव के लिए नया नारा भी गढ़ लिया है। साफ नीयत सही विकास, 2019 में फिर मोदी सरकार। लेकिन जनता इन चार साल के काम काज पर सरकार को कितने नंबर देती है? क्या लोग सरकार के काम काज से खुश हैं? क्या वो फिर इसी सरकार को और बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार हैं? क्या नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की लोकप्रियता में कोई अंतर आया है? इन्हीं सारे सवालों को लेकर सीएसडीएस और लोकनीति ने सर्वे किया है। 2014 में एनडीए को 323 सीटें मिली थीं, और यूपीए 60 तक सिमट गई थी। लेकिन अगर आज चुनाव होते हैं तो एनडीए को बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 2 ज्यादा, यानि 274 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि गिरते पड़ते ही सही, सरकार वापस एनडीए की बन सकती है। यूपीए को आज की तारीख में 164 सीटें मिलने का अनुमान है कि यानि पिछली बार के मुकाबले बढ़ा फायदा और अन्य दलों के खाले में पिछली बार के 153 के मुकाबले, 105 सीटें आ सकती हैं, जिनमें से कई कांग्रेस या यूपीए के साथ जा सकते हैं। कर्नाटक फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो टक्कर कांटे की हो सकती है, अगर चुनाव का एजेंड सिर्फ बीजेपी और मोदी को सत्ता से बाहर रखने का हो।

एच-4 वीजा नियमों में बदलाव की प्रक्रिया आखिरी दौर में

वॉशिंगटन। अमेरिका में एच-4 वीजा के कुछ कैटेगरी के वर्क परमिट खत्म करने की प्रक्रिया आखिरी दौर में है। ट्रम्प प्रशासन ने यह बात गुरुवार को फेडरल कोर्ट में बताई। इस फैसले का असर अमेरिका में काम करने वाले करीब 70 हजार भारतीयों पर पड़ेगा। नए नियमों का औपचारिक प्रशासन जून में जारी हो सकता है। बता दें कि यह वीजा एच-1बी वीजा धारकों के पति/पत्नी को दिया जाता है। फिलहाल, इस वीजा पर काम करने वाले 93 फीसदी लोग भारतीय हैं। प्रस्ताव पास होने के बाद इसका रिस्क होगा : न्यूज एजेंसी के मुताबिक, ट्रम्प प्रशासन ने कोर्ट को बताया कि प्रस्ताव को डिफाईनेट ऑफ होमलैंड सिक््युरिटी (डीएचएस) से मंजूरी मिलने के बाद इसे रेग्युलेटरी एंड प्लानिंग रिस्क के लिए बजट और मैनेजमेंट ऑफिस के पास भेजा जाएगा। इससे पहले डीएचएस ने

कोर्ट में एच-4 वीजा के नए नियमों की छपाई कराने के संकेत भी दिए थे। एच-4 वीजा धारकों में 93 फीसदी भारतीय : एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में एच-4 वीजा पर काम करने वाले करीब 1 लाख लोगों में से 93 फीसदी भारतीय हैं। ट्रम्प प्रशासन के इस फैसले का असर 70 हजार भारतीय पर पड़ेगा। ओबामा सरकार के 2015 में जारी नियम से परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस हासिल करने के इच्छुक एच-4 वीजा धारकों के पति/पत्नीसद्वी के लिए वर्क परमिट हासिल करने का रास्ता साफ हुआ था। जिसके बिना वह नौकरी नहीं कर सकते थे। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेस (यूएससीआईएस) के डायरेक्टर भी इस मसले पर सीनेटर चुक ग्रासले को चिढ़ी लिखकर चिंता जता चुके हैं।

मायावती का बंगला बचाने के लिए अब योगी से मिले सतीशचंद्र मिश्र



लखनऊ। पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास खाली कराए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की अध्यक्ष मायावती को लखनऊ स्थित अपना बंगला बचाने के लिए हर जतन कर रही हैं। पहले तो मायावती ने 13 ए. माल एवेन्यू सरकारी आवास के बाहर कांशीराम यादगार विश्राम स्थल का बोर्ड लगवा दिया और अब उनके बेटे बंधु बंधु सतीश चंद्र मिश्र ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र गुरुवार दोपहर को एनेक्सी भवन पहुंचे और यहां योगी आदित्यनाथ से भेंट की। योगी से मिलकर लौटे सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि उनकी सीएम योगी के साथ यादगार मुलाकात हुई। वह उनसे 13 ए. माल एवेन्यू कांशीराम यादगार स्थल को लेकर मिले थे। उन्होंने यह बंगला वापस न लेने के लिए योगी को प्रत्यावेदन सौंपा है। सतीश चंद्र मिश्र के साथ एवेन्यू के बाहर कांशीराम यादगार विश्राम स्थल का बोर्ड लगवा दिया। माना जा रहा है कि यदि इस बंगले को कांशीराम विश्राम स्थल के नाम कर दिया जाता है तो मायावती को इसे खाली नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, उस स्थिति में उन्हें कैबिनेट में निर्णय लिया गया था कि पूरा बंगला कांशीराम यादगार स्थल के नाम से रहेगा और मायावती उसके छोटे से भाग में रहेंगी। दूसरे आदेश में कहा गया था कि मायावती के आवास छोड़ने के बाद किसी दूसरे को वह आवास अलॉट नहीं किया जाएगा। ... तो बंगला मायावती को खाली नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि जब मायावती यूपी की मुख्यमंत्री थीं तो उनके बंगले के पास ही कांशीराम विश्राम स्थल का बोर्ड लगवा दिया और अब उनके बेटे बंधु बंधु सतीश चंद्र मिश्र ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। इसके पीछे वजह यह थी कि उस वक्त कांशीराम विश्राम स्थल का मासिक किराया करीब 72 हजार था, वहीं मायावती के बंगले का मासिक किराया 4212 रुपये के लिए दोनो (बंगला और कांशीराम विश्राम स्थल) को एकीकृत कर दिया गया। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बंगले खाली करने की कवायद चल रही है, तो मायावती ने 13 ए. माल एवेन्यू के बाहर कांशीराम यादगार विश्राम स्थल का बोर्ड लगवा दिया। माना जा रहा है कि यदि इस बंगले को कांशीराम विश्राम स्थल के नाम कर दिया जाता है तो मायावती को इसे खाली नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, उस स्थिति में उन्हें कैबिनेट में निर्णय लिया गया था कि पूरा बंगला कांशीराम यादगार

जनता से पैसे जुटाकर 2019 में वापसी करेंगे: शशि थरूर

नई दिल्ली। आर्थिक तंगी से जुड़ा रही कांग्रेस अब देश के आम लोगों से चंदा मांग रही है। इसके लिए पार्टी ने ऑफिशियल टिवटर हैंडल के जरिए डोनेशन फॉर्म का लिंक शेयर किया है। इसमें लिखा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारी मदद करें। शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने कहा कि भाजपा सत्ता में है, इसलिए उन्हें ज्यादा चंदा मिल रहा है। बाकी विपक्षी दलों के पास फंड की कमी आ गई है। हम जनता से चंदा जुटाएंगे और इसी से फिर 2019 में कांग्रेस वापसी करेंगे। पिछले दिनों मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए थरूर ने सलाह दी थी कि पार्टी टिवटर पर चंदा की अपील करे।



कांग्रेस ने टिवटर पर लोगों से मांगा चंदा

गई है। कर्नाटक में हमारे ज्यादातर उम्मीदवारों ने अपने खर्च पर चुनाव लड़ा। एक मामले में हमने जनता से चंदा जुटाने का प्रयास किया, जो कामयाब रहा। हो सकता है इसे आम चुनाव में भी इस्तेमाल किया जाए। केरल में भी हम यात्राएं कर फंड जुटाने में सफल हुए। इसी से देश में फिर हमारी वापसी होगी। टिवटर पर लोगों से चंदा मांग रही कांग्रेस : फंड की कमी दूर करने के लिए कांग्रेस ने जनता से सहयोग की अपील की। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल टिवटर हैंडल के जरिए डोनेशन फॉर्म का लिंक शेयर किया है। कांग्रेस ने हैंगोट के साथ ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस को आपका समर्थन और मदद चाहिए। 70 साल पुराने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना छोटा योगदान देकर मदद करें। बता दें कि बुधवार को शशि थरूर ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट कर इसके लिए सुझाव दिया था। कांग्रेस ने डोनेशन फॉर्म में 250 रुपये से लेकर 10 हजार तक के चंदा का विकल्प लोगों को दिया है।

हाईकोर्ट ने जांच संबंधी अर्जी पर फैसले का जिम्मा एनएचआरसी पर डाला

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के तृतीकोरिन में वेदांता की स्ट्रलाइट कॉपर संयंत्र के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान पुलिस गोलीबारी में हुई लोगों की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग संबंधी एक वकील की अर्जी पर निर्णय लेने का जिम्मा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) पर डाल दिया है। न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने कहा कि एनएचआरसी पहले ही इस मामले को अपने हाथ में ले चुकी है और उसने राज्य के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट मांगी है और तमिलनाडु के याचिकाकर्ता वकील को उपयुक्त निर्देश हासिल करने के लिए उसके समक्ष उपस्थित होने को कहा है। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता का आवेदन 29 मई को आयोग के सामने समुचित निर्देश के लिए रखा जाए। तृतीकोरिन में प्रदूषण की चिंता से स्ट्रलाइट कॉपर फैक्ट्री को बंद करने की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन के दौरान 22 मई को हिंसा फैल गई थी और पुलिस गोलीबारी में 10 लोगों की जान चली गई थी। यह प्रदर्शन तीन महीने से चल रहा था। एक

अधिवक्ता ए. राजराजन ने इस मामले में एनएचआरसी के सीधे हस्तक्षेप का निर्देश देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि उन्होंने इस गैरकानूनी हत्या में यथाशीघ्र दखल की मांग करते हुए 23 मई को आयोग को आवेदन दिया था लेकिन आयोग ने इसे अत्यावश्यक मामला मानने से इनकार कर दिया था और जमीनी हकीकत की अनदेखी की थी। वेदांता के चेयरमैन ने जताया दुख : वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि कंपनी लोगों की मर्जी से संयंत्र में फिर से काम शुरू करना चाहती है। अग्रवाल ने कहा कि घटना के बारे में सुनकर ही दुखी हूँ। यह वाक्य में दुर्भाग्यपूर्ण है। पीड़ित परिवारों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। उन्होंने दावा किया कि कंपनी न्यायालय और सरकार के आदेश का कड़ा से पालन कर रही है। हम हमेशा से यह सुनिश्चित करते आए हैं कि तृतीकोरिन के लोग हमारे साथ समृद्ध हों, हम यहां के लोगों को लेकर प्रतिबद्ध हैं और उनकी इच्छा से फिर से कारोबार शुरू करना चाहते हैं।

प्रथम पृष्ठ का शेष

प्रदेश को कुपोषण मुक्ति अभियान के... जशपुर, कांकर, दतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, नागयणपुर, रायपुर, बमेतरा, बालोद, सुकमा, कोण्डागांव, गरियाबंद और बलौदाबाजार-भाटायारा जिले शामिल हैं। इन चयनित जिलों की 134 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत 28 हजार 682 आंगनवाड़ी केन्द्रों में इक्षिप परियोजना का संचालन किया जा रहा है। इक्षिप परियोजना के तहत बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार ने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इक्षिप में शामिल 17 जिलों के सभी 28 हजार 682 आंगनवाड़ी केन्द्रों में हर महीने सुपोषण चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक एवं पारंपरिक गतिविधियां जैसे-गोद भराई, बच्चों के अन्न प्रार्थन और बाल भोज आदि शामिल हैं। कुपोषण के प्रति समाज को और विशेष रूप से माताओं को सचेत करना और जागरूक बनाना सुपोषण चौपाल का मुख्य उद्देश्य है। इसमें बच्चों के अन्न प्रार्थन के जरिए उनकी माताओं को पौष्टिक आहार का महत्व बताया जाता है। गोद भराई की रस्म का उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान माताओं के खान-पान और उनकी अच्छी देखभाल के महत्व से परिवारों को जागरूक करना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल और टैबलेट भी दिए : अधिकारियों ने बताया कि इक्षिप परियोजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन और पर्सनल कंप्यूटर टैबलेट भी दिए गए हैं। उनके लिए मोबाइल एप भी तैयार किया गया है। इससे वे अपने-अपने आंगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों और उनकी माताओं के कुपोषण की स्थिति में सुधार के बारे में मोबाइल एप के जरिए ऑनलाइन रिपोर्ट अपने विभाग

को भेज सकेंगे। छग में कांग्रेस नहीं करेगी गठबंधन... इस मौके पर पूर्व जिला कांग्रेसध्यक्ष मोहन लालवानी, विजय देवांगन, हरमिंदर छाबड़ा, आनंद पवार, नीशु चंद्रकर, पंकज महावर, युनुस गौड़, योगेश लाल, दुष्यंत घोरपड़े, विक्रान्त शर्मा, सलीम गौड़ समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। सीएम हाउस से शुरू हो जांच : पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में सेक्स सीडी कांड की जांच सीएम हाउस से शुरू होनी चाहिए, लेकिन इस केस में उल्टे किसी और को फंसाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ रमनसिंह के दामाद पर आरोप लगाते हुए कहा कि इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी बैंक में 21 करोड़ का चोटाला हुआ। जांच के दौरान बकायदा नार्को टेस्ट भी किया गया, जिसकी कॉपी रायपुर कोतवाली में भूल खाते पड़े हैं। इसके बाद भी इस कांड में सलिस लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। पाक शांति चाहता है तो आतंकी भेजना... तो हमारी तरफ से कार्रवाई की जाएगी। जनरल रावत ने कहा कि शांति के लिए जरूरी है कि सीमा पार से आतंकवाद का खात्मा हो। सेना प्रमुख ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियान रोकने की पहल का मकसद है कि लोगों को शांति का फायदा मिले। उन्होंने कहा कि अगर शांति का यह माहौल कायम रहा तो मैं आपको आश्चर्य करता हूँ कि हम एनआईसीओ (अभियान की शुरुआत नहीं) को जारी रखने के बारे में विचार करेंगे लेकिन आतंकवादियों ने कोई हकत की तो हमें इस संसर्ग विषम या अभियान रोकने या एनआईसीओ पर फिर से सोचना

होगा। सेक्स सीडी कांड: कारोबारी नाटिया के... सहयोग करने की बात कही। इससे पहले सीबीआई ने गुरुवार को भी पूछताछ जारी रखी। कांग्रेस प्रवक्ता आपी सिंह और दो अन्य लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस ट्राजिट मेस बुलाया गया। कांग्रेस नेता के अलावा दो लोग भिलाई के एक कारोबारी के सहयोगी बताए जा रहे हैं। तीनों से अलग-अलग पूछताछ हुई और उनके बयान रिकॉर्ड किए गए। वहीं बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के बयान की जानकारी सीबीआई मुख्यालय को भेज दी गई। बताया जा रहा है कि एजेंसी इस पूछताछ में सीडी के स्रोत और उसे पहचाने वार सार्वजनिक करने वाले व्यक्ति की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी ने किया 27 हजार करोड़... सबका विकास की बात करते हैं। तय समय सीमा के पहले 18 हजार गांवों में बिजली पहुंचा दी है। पहले किसी को फुर्सत नहीं थी कि पूछे के आजादी के बाद भी वहां बिजली क्यों नहीं गई। हमने बीड़ा उड़ाया तो परिणाम सामने है। मेजर गोगाई के खिलाफ सेना ने दिया... मैजिस्ट्रेट के सामने महिला का बयान दर्ज कराए जाने के बाद उन्हें भी छोड़ दिया गया। तमाम दस्तावेजों के आधार पर उन्हें साबित हुआ है कि महिला नाबालिग नहीं है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन महिला के परिवार की मांग है कि यह केस बंद कर दिया जाए।

सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत, सात घायल

सांबा। जिला सांबा के टपेयाल (घगवाल) में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई जबकि सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा वीरवार व शुक्रवार की मध्यरात्रि लगभग दो बजे हुआ जब इनोवा कार नंबर डीएल4सीएई- 6465 जोकि कश्मीर से पंजाब की ओर जा रही थी कि घाघवाल के टपेयाल में पहुंचते ही कार सड़क के किनारे पैराफिट से टकरा गई। यह सड़क हादसा इतना जोरदार हुआ कि गाड़ी के परखचे उड़ गए और उसमें सवार सभी लोग बुरी तरह से घायल हो गए।

CHHATTISGARH STATE POWER DISTRIBUTION COMPANY LTD.
NOTICE INVITING TENDER
 Online bids are invited through CSPDCL e-bidding system (SAP SRM) from eligible Electrical contractors. Registered in the O/o CE (STRE) CSPDCL, Gadhigari, Raipur for following work under jurisdiction of S.E. City Circle-I, CSPDCL, Raipur. Please note that rates quoted shall be exclusive of GST (in both material and service portions) and rates are based on SOR 17-18 (revised) The due date for submission/Opening of the tender is indicated hereunder:-

Tender No.	Name of work	Contract Value (Rs. in lacs)
10-10/Pur/ TR-99 Dt. 25.05.18	For shifting of 33 KV, 11 KV, X'mer DP and LT line due to prop. 4 lane Road from Rajendra Nagar Sub-station to Canal Road by PWD at new Rajendra Nagar Raipur City Dn. South, CSPDCL, Raipur. Estimate no. 76-035-5156-17-0018 dt. 01.09.2017 Rs. 45,83,107/- 1.33 KV/0.24 km. (double ckt) & 0.1 km (single ckt) 2. 33 KV line DP 01 No. 3. 11 KV line 0.680 km. double ckt. & 0.24 km. single ckt. 4. X'mer DP 06 Nos. 5. X'mer on single pole 3 nos. 6. 11 KV DP 02 nos. 7. LT line 0.84 km. 8. 11 KV line on AB cable 0.24 km (shifting)	18.43
10-10/Pur/ TR-99 Dt. 25.05.18	For providing spare 11 KV AB cable in addition with existing 11 KV AB cable in 11 KV feeder at various location under Ganj Zone City Dn. Central CSPDCL, Raipur. Estimate No. 46-028-5160-18-0001 dt. 10.04.2018 Rs. 18,52,592.00	13.05
10-10/Pur/ TR-100 Dt. 25.05.18	For providing new HT conn. 150 KVA 11 KV supply to M/s. Commissioner, Municipal Corporation Raipur for Subhash Stadium Front of Moh Bag Raipur under City Central Dn. CSPDCL, Raipur. Estimate No. 76-062-5160-18-0001 dt. 9,49,614.00. 1.11KV U/G cable 95 sq. mm. 184 M.	7.72

Note:- 1. Last date & Time of submission of bid is on 04.06.2018 up to 01:30 PM and bids will be opened at 02:00 PM. 2. For details visit http://www.cspdccl.co.in->cerr department and http://www.cspdccl.co.in->e-bidding portal. 3. For Bidding CSPDCL Helpline no. 0771-2578672 (ETC, CSPDCL) & Corresponding Cancellation/extension of time extending in any, will be displayed on above website. E-mail ID-secr.raipur@cspdccl.in (R.A. Pathak- 92489787) **Save energy for benefit of self and Nation** Superintending Engineer City Circle-I, CSPDCL, Raipur S-65690/3

उद्योषणा
 सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक मोहरदास पिता नामसिंह निवासी लटुवा ने आवेदन किया है कि आवेदक को युवा धानबाई की मृत्यु दि. 15/05/2002 लटुवा में हुआ। निम्नका पंजीयन नहीं होने के कारण मृत्यु पंजीयन किये जाने का निवेदन किया है। जो इस न्यायालय में विचारणीय है। उक्त संबंध में किसी को कोई आपत्ति/बाधा पेश करना हो तो स्वयं अथवा किसी अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 29.05.18 के पूर्व प्रस्तुत किया जा सकता है। निम्न अधिवक्ता के आवासीय-दवा पर विचार नहीं किया जाएगा।
 उक्त उद्योषणा आज दिनांक 14.05.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर सहित जारी किया गया।
 तहसीलवार जिला बलौदाबाजार